LOK SABHA

Friday, August 4, 1967/Sravana 13, 1889 (Saka).

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

Re. Q. 1587

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न में एक छपाई की ग़लती दिखाई देरही है। इसमें "41½ परसेंट" के स्थान पर "4½ परसेंट" होना चाहिये। मैं पहले ही यह बता देना चाहता हूं ,ताकि इसके लिए कहीं मुझे दोषी न ठहराया जाये।

Increase in the price of Controlled varieties of Cloth

+

*1587. **Shri Madhu Limaye:***
Shri S. M. Banerjee:
Dr. Ram Manohar Lohia:
***Shri George Fernandes:** ..*
Shri Ram Sewak Yadav:

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether Government have taken a decision to increase the price of the controlled varieties of cloth by 4-1|2 per cent;

(b) whether this increase will not give a spurt to prices of other articles of consumption; and

(c) its general impact on the cost of living index and on the demands for increase in D.A. by Government and non-Government Employees?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh): (a) There is no such proposal. Government are not considering any increase in the price of the controlled varieties of cloth.

(b) and (c). Do not arise.

श्री मधु लिमये : सरकार नियंत्रित कपड़े के दामों के बारे में समय समय पर इत्तिला देती रहती है। जब उसका दाम बढ़ाया जाता है, तो उस वक्त भी इत्तिला दी जाती है, जैसे कि अप्रैल में दी गई थी। मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछले दस वर्षों में फ़ाइन और सुपर-फ़ाइन कपड़े के दामों में क्या परिवर्तन हुआ है, कितनी वृद्धि हुई है। क्या सरकार ने इसके बारे में कोई आंकड़े इकट्ठे किये हैं? जब मिल वालों की ओर से नियंत्रित कपड़े के दाम में वृद्धि करने की मांग की जाती है, तो कहा जाता है कि बड़ा घाटा है, यह है, वह है। लेकिन ये लोग कभी नहीं बताते कि फ़ाइन और सुपर-फ़ाइन कपड़े में वे कितना मुनाफ़ा कमा रहे हैं। क्या मंत्री महोदय पिछले दस सालों के बारे में दाम वृद्धि सम्बन्धी कोई जानकारी देंगे? मैं ने कई बार यह जानकारी हासिल करने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक मुझे इसमें सफलता नहीं मिली है।

श्री दिनेश सिंह : जो कपड़ा हम ने कंट्रोल कर रखा है, नियंत्रित कर रखा है, वह कपड़े की बनावट के हिसाब से नहीं है, बल्कि कुछ ख़ास चीजें हैं, जैसे धोती, साड़ी, लांग क्लाथ, कमीज का कपड़ा, ड्रिल। इस में कोर्स, फ़ाइन और सुपर-फ़ाइन सब आ जाते हैं। माननीय सदस्य का सवाल मेरे ख़याल में यह है कि जो कपड़ा नियंत्रित नहीं है, उसके दामों में क्या वृद्धि हुई है। यह सूचना इस वक्त मेरे पास नहीं है, लेकिन पूरे काटन मैन्यू-फ़ैक्चर का जो दाम बढ़ा है, उसकी सूचना मैं दे सकता हूं। 1952–53 के बस के हिसाब से उसका इन्डैक्स नम्बर 1961–62 में 127.9 था और इस वक्त वह बढ़ कर 150.8 हो गया है। माननीय सदस्य ने जो सूचना मांगी है, वह पता लगा कर मैं उनको देने की कोशिश करूंगा।

श्री मधु लिमये : केवल मुझे नहीं, सारे सदन को। सब को एनलाइटन करना चाहिए।

श्री दिनेश सिंह : अगर मैं माननीय सदस्य को दे दूंगा, तो सब को मालूम हो जायेगा।

श्री मधु लिमये : मेरे पास इकानोमिक टाइम्स का 23 अप्रैल का अंक है। उसमें कुछ कम्पनियों के बारे में मुनाफ़े आदि के सम्बन्ध में आंकड़े दिये गये हैं। मिल के मालिक हमेशा चिल्लाते रहते हैं कि उनकी बहुत तकलीफें हैं। उस पत्रिका में पच्चीस सूती मिलों का हिसाब दिया गया है और उन में से एक भी मिल ऐसी नहीं है, जिसका ग्रास प्राफ़िट वर्ष पहले की तुलना में ताजा साल में घटा है। बल्कि मैं ने जल्दी में यह हिसाब लगाया है कि पहले वर्ष मुनाफ़ा करीब करीब 20 करोड़ रुपया था और उसके बाद ताजा वर्ष में करीब करीब 30 करोड़ रुपये का मुनाफ़ा हुआ है, अर्थात् उनका मुनाफ़ा करीब 10 करोड़ रुपये बढ़ गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार रुई के दामों पर नियंत्रण को हटाने के सम्बन्ध में क्या करने जा रही है। मेरी राय है कि रुई के अधिकतम दाम नियंत्रण हटाना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ कपड़े के दाम में वृद्धि न हो, उसके लिये सरकार क्या इन्तजाम करेगी, ताकि किसानों को तो ज्यादा मूल्य मिले, लेकिन ग्राहक को ज्यादा मुल्य न देना पड़े। मिलों के मुनाफ़े बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और नियंत्रित, फ़ाइन या सुपर-फ़ाइन, किसी भी कपड़े का दाम बढ़ाने के लिये उनके पास कोई केस नहीं है।

श्री दिनेश सिंह : माननीय सदस्य ने जो बताया है, उसके हिसाब से मैं जानता हूं कि मिल-मालिकों को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। उनको कितना मुनाफ़ा हुआ है, ये आंकड़े तो मैं पता लगा कर ही बता सकूंगा। जहां तक रुई का सम्बन्ध है, मैं सदन में बहुत शीघ्र ही बताऊंगा कि इस सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या होगी। इस वक्त मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार की जो नीति होगी, हमें विश्वास है कि वह हमारे किसान भाइयों के हित में होगी, जो रुई को पैदा करते हैं। जहां तक कपड़े की कीमत बढ़ने का सवाल है, नियंत्रित हिस्से . . . .

श्री मधु लिमये: मैं पूरे कपड़े की बात कर रहा हूं।

श्री दिनेश सिंह : नियंत्रित हिस्से के दाम तो हम बढ़ने नहीं देंगे। जो नियंत्रित नहीं है, वह सीधे हमारे कंट्रोल में नहीं आता है। यह भी कहा जाता है कि सब कपड़े को नियंत्रित किया जाये। लेकिन हम यह सोचते हैं कि जो आम जनता के इस्तेमाल का कपड़ा है, जो नियंत्रित है, उसके दाम हमको रोकने चाहिए और उसके दाम हम ने रोके हैं। बाकी कपड़े के लिए मार्केट में सप्लाई और डिमांड का सिद्धान्त है। अगर जनता यह महसूस करेगी कि हम को इस के दाम और नहीं देने चाहिएं, तो वे दाम ज्यादा नहीं बढ़ पायेंगे।

Shri S. M. Banerjee: I would like to know whether it has been brought to the notice of the Hon. Minister that though the prices of the controlled varieties of cloth are stamped on them, during any festival, whether Diwali, Holi or Id, the prices go up at least by 10 per cent even of the medium and coarse cloth which are supposed to be controlled items. I would like to know what steps Government contemplate to take with the help of the State Governments to see that the prices are the same as those stamped on the cloth, that they do not increase, and whether any apparatus is there either with the Central Government or with the State Government to see that the prices of fine and superfine cloth are not increased abnormally high.

श्री दिनेश सिंह : इसका नियंत्रण हम प्रदेश सरकारों की मदद से करते हैं। समय समय पर प्रदेश सरकारों के इंसपैक्टर जा कर चैक करते हैं। प्रदेश सरकारें हम को रिपोर्ट्स भेजती रहती हैं कि शहरों में इन कपड़ों का स्टाक काफ़ी है या नहीं, क्या वे दुकानों पर

मिल रहे हैं और किस दाम पर मिल रहे हैं, आदि। अगर कोई ख़ास शिकायत आती है, तो उसकी जांच की जाती है। इस बीच प्रदेश सरकारों से जो रिपोर्ट्स आई हैं, उनमें मैं ने देखा है कि आजकल शिकायतें कोई ज्यादा नहीं हो रही हैं।

श्री जार्ज फ़रनेन्डीज : लोक-सभा के पिछले सेशन में यह बताया गया था कि मिल-मालिकों की ओर से कपड़े का दाम 9 प्रतिशत बढ़ाने की मांग की गई थी और बाद में जैसे ही अधिवेशन ख़त्म हुआ, तो सरकार की ओर से कपड़े का दाम साढ़े चार या पांच प्रतिशत बढ़ाने की इजाजत दे दी गई थी। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या अप्रैल के बाद मिल-मालिकों की ओर से सरकार के पास कपड़े के दाम और बढ़ाने के लिये कोई निवेदन आया है, अथवा चूंकि सरकार ने उनकी पहली मांग को सिर्फ़ आधा पूरा किया था, इसलिए क्या उस मांग को पूरा करने के बारे में कोई निवेदन आया है ?

श्री दिनेश सिंह : माननीय सदस्य जानते हैं कि हर छः महीने के बाद—अप्रैल और अक्तूबर में—कपड़े के दाम के बढ़ने की बात उठती है। अप्रैल में कपड़े की कीमत साढ़े चार फ़ीसदी बढ़ी थी, जिसके बारे में मैंने सदन में कहा था। अक्तूबर की बात आगे आयेगी, लेकिन, जैसा कि मैं ने अभी सदन में कहा है, हम कपड़े की कीमत और बढ़ाने की इजाजत नहीं देंगे।

Shri S. K. Tapuriah: Though my hon. friend Shri Madhu Limaye has just now cited that the profits have gone up, what he has not mentioned, is that most of the mills which he mentioned from the statement are not purely cotton textile mills, but also subsist as a man-made fibre industry, and the profits have not considerably gone up of cotton textiles. May I ask the Minister whether it is a fact that the return on the cotton textile mills only as compared to the investment has gone down, and also as compared to the increase in the sale over the period, the percentage of return has gone down or not?

Shri Dinesh Singh: All these are various statistics that come from time to time, but we should look at the general prosperity which I do not think has gone down where individual units are concerned; there are, on the other hand, certain smaller textile mills, what we call the marginal and weak textile mills. They are certainly affected.

Shri Anantrao Patil: May I know whether there is any possibility of increase in the price of controlled cloth by the expected increase in the floor price of cotton, and if so, what will be the percentage?

Shri Dinesh Singh: I would request the hon. Member to wait till I announce the cotton policy.

Shri M. Amersey: In consideration of the general demand of the House that the cloth prices should be reduced, will the Government think of reducing the very heavy excise duties which are a big portion in the make-up of cloth prices?

Shri Dinesh Singh: No such reduction is contemplated.

Shri A. S. Saigal: May I know whether the Government is contemplating to appoint a committee to look after the prices of cotton which are being increased day by day?

Shri Dinesh Singh: There is a Cotton Advisory Committee; it advises us on this matter, and no other committee for this specific purpose is contemplated.

Shri H. N. Mukerjee: In view of the fact that in a couple of months' time there would come the Puja in West Bengal, and Dusserah all over the country and Diwali shortly to follow, may I know if the Government is going to take special care to see that the rise in prices, if it is

unavoidable, is not beyond the limit which our people can endure in the present circumstances?

Shri Dinesh Singh: I said just now that we are not contemplating any rise in prices, and we shall look into the question of extra supply. Usually, the mills themselves arrange more supplies on these occasions.

श्री एम० एस० जोशी : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बता सकेंगे कि क्योंकि अभी आप ने फरमाया कि हमारे जो कर्मचारी हैं वह वहां जा कर चेकिंग करते हैं कि जो प्राइस प्राइसेज बंधी हुई हैं उसके ऊपर अमल हो रहा है या नहीं और उसके साथ साथ आप ने यह भी बताया कि हमारे कर्मचारी यह भी बताते हैं कि कितनी दूकानों में माल है कितनी में नहीं है, तो मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या आप के कर्मचारियों ने आप को यह भी बताया है कि जब होली, दीवाली और ईद वगैरह होते हैं तब ऐन वक्त पर दूकानों पर माल नहीं रहता है ?

श्री दिनेश सिंह : कर्मचारी तो मैं ने अर्ज किया अध्यक्ष महोदय, प्रदेश सरकार के होते हैं। वह वहां पर जा कर देखते हैं कि कोई शिकायत है या किस कीमत पर कपड़ा बिक रहा है। जहां तक कि खास खास वक्त का है मैं ने अर्ज किया कि मिल वाले खुद ही स्टाक ज्यादा रिलीज करते हैं ताकि जो बड़े त्यौहार हों या जिस वक्त कि कपड़ा ज्यादा खरीदा जाता है उस वक्त वह ज्यादा मिल सके।

Shri Ranga: In view of the fact that the cotton growers have been complaining for a long time that the ceiling price that has been fixed is not reasonably high and the millowners themselves have represented to Government to allow this ceiling to be raised and in view, further, of the fact that the superfine and fine cloth are purchased only by the upper middle-class people and the rich people, why is it that the Government do not think in terms of allowing the ceiling price for cotton to be raised and not bother about the price of these superfine and fine cloth prices?

Shri Dinesh Singh: The only point in this connection is that the coarse is made out of the same cotton. It is a question of increase of ceiling of all cotton, which will mean also an increase in the ceiling price of cotton which is used for producing the other varieties—(*Interruption*)

Shri Ranga: It depends on the staple used.

Shri Dinesh Singh: The general demand, which Prof. Ranga knows, is that they want us to do away with the ceiling price of cotton so that the cotton growers may have enough as the market demands, which will also mean that the rise in the price of cotton that is used is also for the coarse cloth; not only for superfine and fine cloth. That is the only point. But I would beg of the House to wait till I announce the policy.

Dr. A. G. Sonar: What is the percentage of cloth that has been controlled?

Shri Dinesh Singh: Approximately 40 per cent of the mill-made one.

Shri Lobo Prabhu: May I enquire from the hon. Minister if the price of cloth is not largely influenced by Government policy? I refer to the cost added to the cloth, call it cess or subsidy; the Khadi subsidy, the handloom subsidy. I refer to the cost added to the cloth, it cess or sub-lower price of controlled cloth. Therefore, I am not referring to the question already asked about that. May I enquire from the Minister whether he would make it clear to the public of this country that 60 per cent—I have made some calculations—of the price of cloth is not paid either to the grower or to the manufacturer or to the dealer, but is paid to Government?

Shri Dinesh Singh: Whatever does not go to the manufacturer or dealer or producer goes to the people of the country.

श्री राम सेवक यादव : मंत्री जी ने बताया कि हमारे कर्मचारी मूल्यों को चेक करने के लिये जाते हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी चीजें भी सामने आईं कि जो नियंत्रित दाम हैं उन से अधिक कपड़े पर छपा रहता है और यदि हां, तो ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई और मैं यह भी बता दूं कि यहां पर ऐसी चीजों के दाम जो ज्यादा छपे हैं उनका प्रदर्शन भी किया गया है सदन में ।

श्री विनेश सिंह : किसी खास बात की शिकायत करें अध्यक्ष महोदय, तो मैं नहीं कह सकता लेकिन बाकी जितनी शिकायतें हैं उनको देखा जाता है । जो आमदनी होती है और जो दाम बनते हैं उनको देखते हैं ।

श्री मधु लिमये : मिल वालों को उसी कपड़े का ज्यादा दाम मिलता है ।

डा० सुशीला नायर : श्रीमन्, यह क्या सही नहीं है कि जो खादी को सबसिडी दी जाती है वह जो अनेक प्रकार से हिडेन सबसिडी मिल वालों को दी जाती है उससे कई दर्जे कम है, यह फैक्ट्स ऐंड फिगर्स क्या गवर्नमेंट इकट्ठा कर चुकी ?

श्री विनेश सिंह : हिडेन सबसिडी की बात तो मैं नहीं कह सकता अध्यक्ष महोदय । हम कोई हिडेन सबसिडी तो देते नहीं हैं । खादी को जो सबसिडी देते हैं उसके बारे में सदन को मालूम है ।

डा० सुशीला नायर : हिडेन सबसिडी से मेरा मतलब है कि जो उनको ट्रांसपोर्ट में फैसिलिटी होती है, मशीनरी में होती है, कई एक चीजों में सहायता की जाती है । यह तो काफी लम्बा किस्सा है इस सदन में आ चुका है कि बहुत प्रकार से उनको सबसिडी मिलती है ।

Fixation of Fair Price of Rubber

*1588. **Shri Ram Kishan Gupta:***
Shri K. M. Abraham:
Shri Vasudevan Nair:
Shri C. Janardhanan:
Shri P. C. Adichan:
Shri Bhogendra Jha:
Shri Yashpal Singh:
Shri Ram Gopal Shalwale:
Shri A. Sreedharan:
Shri Mangalathumadam:
Shri K. Lakkappa:
Shri E. K. Nayanar:
Shri Sradhakar Supakar:
Shri P. Viswambharam:

Will the Minister of **Commerce** be pleased to refer to his statement made in Rajya Sabha on the 11th April, 1967 and state:

(a) whether Government have received the report from Tariff Commission regarding the fixation of a fair price for rubber;

(b) if so, the recommendations made therein; and

(c) the action taken thereon?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). The Tariff Commission's report is still under the consideration of Government. A decision is likely to be arrived at shortly. A copy of the Report as also a resolution containing Government's decision thereon will be laid on the Table of the House.

श्री राम किशन गुप्त : मैं जानना चाहता हूं कि नेचुरल रबर की फ्लोर और सीलिंग प्राइसेज क्या हैं ?

श्री विनेश सिंह : सीलिंग प्रोइस रबर की तो मुझे नहीं मालूम है । मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस बदलती रहती हैं मार्केट आपरेशन के हिसाब से ।

श्री राम किशन गुप्त : मैं जानना चाहता हूं कि रबर की कितनी कमी है और सेल्फ